पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल में हो रहा सत्यापन

किसानों की मेहनत पर कंपनियों का मुनाफा

राजू पटेल

खंडवा। जिले में खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही बीज कारोबार को लेकर बड़े खुलासे सामने आने लगे हैं। एक ओर बाजार में सोयाबीन और मक्का बीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग और निजी बीज कंपनियों की कथित सांठगांठ ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं नवभारत कि ग्राउंड रिपोर्ट में किसानों से मिली जानकारी के अनुसार बीज सत्यापन, ट्रायल फील्ड निरीक्षण और टैग जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप सामने आया है।

दावा किया जा रहा है कि नियमों के अनुसार खेतों तक जाकर निरीक्षण करने की प्रक्रिया अब केवल कागजों तक सीमित रह गई है और पूरा खेल प्रति क्विंटल सेटिंग के आधार पर संचालित हो रहा है।

ट्रायल फील्ड के वेरिफिकेशन में बड़ी धांधली, क्या अंधेरे में हैं किसान?

जिले के जिम्मेदार बीज निगम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। खेतों में बोए जाने वाले बीजों के ट्रायल फील्ड यानी जिस खेत में नए बीजों का परीक्षण होता है, उसके वेरिफिकेशन में भारी पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। नियम के मुताबिक, बीज इंस्पेक्टर को मौके पर जाकर तीन बार फसल की जांच करनी होती है और पैकिंग भी अपनी निगरानी में कराकर टैग जारी करना होता है। लेकिन अधिकारियों की कमी का बहाना बनाकर दफ्तर से ही सीधे टैग जारी किए जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा निजी बीज कंपनियां उठा रही हैं। हमारे खेतों में फसल उग रही है, लेकिन मुनाफा दूसरे राज्यों को हो रहा है।

500 प्रति क्विंटल में चल रहा पूरा खेल -अंदरूनी सूत्र ने दावा किया कि बीज कंपनियों और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के बीच प्रति क्विंटल के हिसाब से लेनदेन चलता है। सूत्र के अनुसार कई मामलों में अधिकारी खेतों तक पहुंचे बिना ही कार्यालय में बैठकर कागजी सत्यापन पूरा कर देते हैं। नियमानुसार बीज निरीक्षक को ट्रायल फील्ड का निरीक्षण, रोगिंग और उत्पादन सत्यापन करना चाहिए, लेकिन आरोप है कि निरीक्षण की प्रक्रिया अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है।

खेत देखे बिना जारी हो रहे टैग -सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में फसल की वास्तविक गुणवत्ता और उत्पादन की जांच किए बिना ही पैकिंग टैग जारी कर दिए जाते हैं। विभाग निरीक्षकों की कमी का बहाना बनाकर पूरी व्यवस्था को कागजी बना दिया गया है, जिसका सीधा फायदा निजी बीज कंपनियों को मिल रहा है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल प्रशासनिक

लापरवाही नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और कृषि व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा।

प्रदेश की जमीन, फायदा बाहरी राज्यों को -जानकारी के अनुसार प्रदेश की उपजाऊ जमीन पर तैयार होने वाला उच्च गुणवत्ता का बीज बड़े स्तर पर बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा है। जिसके कारण स्थानीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं मिल पा रहा, जबकि कंपनियां यहां उत्पादन करवाकर बाहर मुनाफा कमा रही हैं।

ट्र बीज और प्रमाणन प्रक्रिया पर सवाल-जिले में ट्र बीजऔर हाईब्रिड बीजों के नाम पैर किसानों से भारी कीमत वसूली जा रही है। सोयाबीन बीज 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक और मक्का बीज 800 से 900 रुपए किलो तक बिक रहा है। किसानों का कहना है कि जब निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है तो गुणवत्ता की गारंटी कैसे मानी जाए। रहा सवाल बीज की कीमतों का तो उस पर भी किसी प्रकाश का कोई नियंत्रण नहीं है। बीज निर्माता विक्रेता समय का फायदा उठा कर मनमाना पैसा वसूल रहे है।

संयुक्त कृषक संगठन ने उठाए सवाल- संयुक्त कृषक संगठन के जिला मंत्री जय पटेल ने पूरे मामले को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कृषि विभाग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि नियमों के अनुसार निरीक्षण हो तो कई कंपनियों की वास्तविकता सामने आ जाएगी।

जय पटेल ने कहा कि किसानों को महंगे दामों पर बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि विभाग कंपनियों और विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देता नजर आ रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

किसानों ने सुनाई अपनी पीड़ा

सखाराम पटेल, किसान- हम लोग कर्ज लेकर महंगा बीज खरीद रहे हैं, लेकिन बीज की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। विभाग सिर्फ कागजों में कार्रवाई करता दिख रहा है।

सुरेश चौहान, किसान-अगर अधिकारी खेतों तक नहीं पहुंच रहे तो फिर निरीक्षण का मतलब क्या रह गया? किसान जोखिम उठाए और कंपनियां मुनाफा कमाएं, यह गलत है।

रामेश्वर पाटीदार, किसान -हर साल बीज के नाम पर किसानों से बड़ी रकम ली जाती है। जब फसल खराब होती है तब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता।

महेश यादव, किसान -खंडवा की जमीन पर तैयार अच्छा बीज बाहर भेज दिया जाता है और स्थानीय किसानों को महंगा और कमजोर माल मिलता है। यह किसानों के साथ सीधा अन्याय है।

निष्पक्ष जांच की मांग तेज -

लगातार सामने आ रहे आरोपों के बाद सयुक्त किसान संगठन ने पूरे मामले की शिकायत अपर कलेक्टर आरसी बडोले से कर निष्पक्ष जांच, बीज कीमतों पर नियंत्रण और बिना निरीक्षण टैग जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

खंडवा में भाजपा के तीन धड़ों में बंटने की चर्चा...

पार्टी विद डिफरेंस अब बनी पार्टी विद डिफरेंसेस

नवभारत न्यूज़

खंडवा। कभी अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती के लिए पहचान रखने वाली भाजपा अब अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। संगठन और सत्ता के बीच बढ़ती दूरी अब सार्वजनिक मंचों और प्रशासनिक फैसलों में भी साफ नजर आने लगी है। जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े की पार्टी बैठक में खुलकर सामने आई नाराजगी के बाद अब विधायक कंचन तनवे के वायरल पत्र ने जिले की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है।राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि खंडवा में भाजपा के भीतर चल रही आपसी खींचतान का असर विकास कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। नगर निगम के करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य अचानक रोक दिए जाने की खबर ने इस चर्चा को और हवा दे दी है।

वायरल पत्र के बाद थमे विकास कार्य -सूत्रों के अनुसार जिन विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वर्क ऑर्डर जारी होने की तैयारी थी, उन्हें अचानक रोक दिया गया। इनमें इंदौर

नाका प्रवेश द्वार निर्माण, सीसी रोड, बाउंड्रीवॉल तथा जिमखाना ग्राउंड से जुड़े कार्य शामिल बताए जा रहे हैं। इन कार्यों के रुकने के पीछे विधायक कंचन तनवे के उस पत्र को वजह माना जा रहा है, जो हाल ही में सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर किसी विवाद से इनकार किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के भीतर बढ़ते शक्ति संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं।

विधायक-महापौर समन्वय पर उठे सवाल-खंडवा की राजनीति में लंबे समय से विधायक कंचन तनवे और महापौर अमृता यादव के बीच समन्वय को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। अब विकास कार्यों पर लगे ब्रेक ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि संगठन और सत्ता के अलग-अलग केंद्र बनने से कई जनप्रतिनिधि खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि नाराजगी अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंच रही है। जिसकी सुगबुगाहट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गई है यही कारण है शुक्रवार को निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मीडिया के सामने सफाई पेश करनी पड़ी।

तीन धड़ों में बंटी नजर आ रही भाजपा-जिले की भाजपा वर्तमान में स्पष्ट रूप से कई गुटों में बंटी दिखाई दे रही है। एक धड़ा वर्तमान नेतृत्व और सत्ता केंद्र के साथ खड़ा नजर आता है, जबकि दूसरा धड़ा लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का बताया जा रहा है। तीसरा वर्ग उन कार्यकर्ताओं का है जो मौजूदा हालात में खुद को असमंजस की स्थिति में महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की कार्यक्रमों से दूरी और कई जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक नाराजगी अब संगठन के भीतर बढ़ती संवादहीनता की ओर इशारा कर रही है।

नंदू भैया की कमी और संवादहीनता की खाई-आज के इस सियासी घमासान में हर कार्यकर्ता को स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान (नंदू भैया) की कमी शिद्दत से खल रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नंदू भैया के पास वह राजनीतिक दक्षता थी जिससे वे सबको साध लेते थे। आज की लीडरशिप में संवाद की जगह आदेश ने ले ली है। जिस तरह जिला अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को सूचना न देना और उसे विधायक से जुड़ी आपसी अनबन का नतीजा माना जाना, यह दर्शाता है कि संगठन अब व्यक्तिगत अहंकार की भेंट चढ़ रहा है।

यही कारण है कि जिले में भाजपा तेजी से उसी गुटबाजी की राह पर चल पड़ी है, जिसका वह कभी कांग्रेस में होने पर मजाक उढ़ाया करती थी। कार्यक्रमों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का भाव और समर्पण गायब है। वरिष्ठों का मौन विरोध और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक नाराजगी यह बताने के लिए काफी है कि खंडवा भाजपा में अब सबकुछ ठीक नहीं है। बहरहाल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच स्व. नंदकुमार सिंह चौहान की राजनीतिक शैली की चर्चा फिर तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके समय में संगठन में संवाद, समन्वय और सामंजस्य की स्थिति बनी रहती थी। मौजूदा हालात में कई कार्यकर्ता निर्णय प्रक्रिया से अलग महसूस कर रहे हैं।

सांसद को करना पड़ा बचाव - मामले को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। वहीं निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा को भी आपसी खींचतान पर सफाई देने पड़ रही है। संगठन और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि विधायक और महापौर के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन वायरल पत्र और रुके हुए विकास कार्यों ने राजनीतिक अटकलों को और मजबूत कर दिया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते संगठन के भीतर बढ़ रही नाराजगी, संवादहीनता और गुटबाजी को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई दे सकता है। खंडवा भाजपा फिलहाल ऐसे दौर से गुजरती दिख रही है, जहां सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

विधायक कंचन तनवे ने ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

नवभारत न्यूज़

खंडवा। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे ने जनपद पंचायत खंडवा में समीक्षा बैठक लेकर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नगर निगम की बैठक में 21 बिंदुओं पर चर्चा के बाद विधायक तनवे ने जनपद पंचायत में 16 प्रमुख बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग तथा लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक तनवे ने अधिकारियों से कहा कि आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी तथा जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनकी 30 दिन बाद प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क निर्माण, खाद्यान्न वितरण एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, जनपद पंचायत खंडवा की सीईओ एवं भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनूप पटेल उपस्थित रहे।

195 वाहन चालकों पर कार्रवाई 3 .36 लाख रुपए जुर्माना

खंडवा। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जिले में संचालित यात्री बसों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान 21 मई से 27 मई तक आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालित किया गया। अभियान के दौरान बसों में अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट, ओवरलोडिंग, इमरजेंसी विंडो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा तथा चालक-परिचालकों की स्थिति एवं व्यवहार की जांच की गई। निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में कुल 195 बस संचालकों से 3 लाख 36 हजार 400 रुपए समन शुल्क वसूला गया।बुधवार को उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय, एआरटीओ दीपक मांझी यातायात प्रभारी देवेंद्रसिंह परिहार एवं यातायात स्टाफ द्वारा ओंकारेश्वर क्षेत्र में बसों और ऑटो की जांच कर 52 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 44 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बस संचालकों को यात्री सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

20 दिवसीय ऑन जॉब प्रशिक्षण पूर्ण, विद्यार्थियों को मिला व्यावसायिक मार्गदर्शन

नवभारत न्यूज़

खंडवा। शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छैगांव माखन के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के हेल्थ केयर और आईटी ट्रेड के विद्यार्थियों ने साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग रामनगर खंडवा एवं दलाल इंस्टिट्यूट खंडवा में 20 दिवसीय ऑन जॉब प्रशिक्षण पूर्ण किया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को साईं नर्सिंग कॉलेज की कार्यप्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व एवं कौशल विकास संबंधी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी पी.एस. सोलंकी एवं जिला व्यावसायिक समन्वयक महेश भगोरे उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों से प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी ली तथा उन्हें भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ अच्छे संस्कार अपनाने का संदेश भी दिया।साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संचालक डॉ. प्रवेश भारद्वाज एवं डॉ. जगदीश कोगे ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यशाला में हेल्थ केयर वोकेशनल ट्रेनर कुमारी रानू मालवीय एवं आईटी वोकेशनल ट्रेनर कुमारी सुनिता द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं विद्यार्थियों को फलदार पौधों का वितरण भी किया गया।

नहाल्दा और कोटवाड़ा में 121 टीबी मरीजों की एक्स-रे जांच की

नवभारत न्यूज़

खण्डवा । सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत शुक्रवार को खण्डवा विकासखण्ड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहाल्दा व कोटवाड़ा में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से नहाल्दा में 59 तथा कोटवाड़ा में 62 संभावित मरीजों की एक्स-रे जांच की गई। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला क्षय अधिकारी डॉ. शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि हैंडहेल्ड एक्स-रे से जांच के साथ-साथ सभी मरीजों के स्पुटम सैंपल भी लिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव मरीजों का तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा। शिविर के दौरान स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जागरूक किया। टीम ने बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, अचानक वजन घटना, लगातार बुखार व कमजोरी टीबी के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। टीबी का पूरा इलाज संभव है और सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपलब्ध है।

मोतियाबिंद की नि :शुल्क जांच के लिए अगले माह में लगेंगे शिविर

नवभारत न्यूज़

खण्डवा। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत चौइथराम फाउण्डेशन ट्रस्ट व शंकरा आई सेन्टर इन्दौर के सहयोग से जिले के विभिन्न ग्रामों में जून माह में मोतियाबिंद जांच शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि इन शिविरों में चयनित मोतियाबिंद मरीजों को नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए भेजा जायेगा।

उन्होंने बताया कि शंकरा आई सेंटर इंदौर के सहयोग से 2 जून को ओंकारेश्वर व धनगांव, 4 जून को पुनासा व अटूटखास, 9 जून को हरसूद, किल्लौद व रोशनी, 11 जून को खालवा व सहेजला, 18 जून को सेंधवाल व गुड़ीखेड़ा, 22 जून को मूंदी व जावर, 24 जून को छैगांवमाखन व पंधाना में नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर लगाए जाएंगे।

इसके अलावा चौइथराम फाउण्डेशन ट्रस्ट इन्दौर के सहयोग से 5 जून को जसवाड़ी व बड़गाँव गुर्जर, 11 जून को मूंदी, 12 जून को पंधाना, 15 जून को छैगांवमाखन, 17 जून को जावर व अमलपुरा, 19 जून को पुनासा व कालमुखी, 22 जून को सुलगांव व मोहना, 24 जून को खालवा व सिंगोट, तथा 29 जून को हरसूद व किल्लौद में नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन कर मरीजों का जांच परीक्षण व उपचार किया जायेगा।

एक नजर विरोध करने पर उपसरपंच अपमानित

किल्लोद में शासकीय नल से वितरित हो रहा है गंदा पानी

नवभारत न्यूज़

किल्लौद। जिले के बलड़ी जनपद से किल्लौद ग्राम पंचायत में लोग नलजल योजना में वितरित हो रहे गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना केवल कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रही है वहीं ग्राम पंचायत किल्लोद में पर्याप्त जल स्रोत होने के बावजूद ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और जो पानी मिल भी रहा है वह अत्यधिक मटमैला और गंदा है।

इस अव्यवस्था से परेशान होकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोलते हुए जनपद पंचायत के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। प्राप्त शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत किल्लोद में पेयजल व्यवस्था की देखरेख और सुचारू संचालन के लिए तीन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन इन कर्मचारियों की घोर लापरवाही और हठधर्मिता के कारण पिछले दो दिनों से गाँव में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ग्रामीण जब इस मटमैले पानी का

विरोध करते हैं, तो ये कर्मचारी सीधे तौर पर धमकी और गालियां देने पर उतारू हो जाते हैं।यह मामला उस समय और अधिक गंभीर हो गया जब किल्लोद के उपसरपंच शंकर कड़ोले ने एक जनप्रतिनिधि के नाते इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जब पानी की टंकी के आसपास फैली भारी गंदगी को हटाने और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा, तो नियुक्त कर्मचारी रामदास राजपूत और सुनील ने सारी हदें पार कर दीं। कर्मचारियों ने सरेआम उपसरपंच को अपमानित करते हुए जातिसूचक गालियां दीं और धमकी भरे लहजे में कहा कि तेरे से जो बने वो मेरा कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। इस दबंगई और दुर्व्यवहार से आक्रोशित होकर उपसरपंच शंकर कड़ोले के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी जैसे रसीद पठान, राजेश, नाना, बद्रीप्रसाद, चरस राम, मनीष और दुगेश लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ के साथ-साथ इस शिकायती पत्र की एक प्रति स्थानीय थाना प्रभारी को भी उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भेजी है।